



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 4—जुलाई 10, 2009 (आषाढ़ 13, 1931)
No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 4—JULY 10, 2009 (ASADHA 13, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 9 जून 2009

सं. एन-15/13/14/8/2008-यो. व वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ उचित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 मई, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा निगम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे अर्थात्

हेन्द

बढ़ते हुए निम्नलिखित क्षेत्र

उत्तमपालयम

जिला तेनी तालुक उत्तमपालयम के राजस्व गाँव

उत्तमपालयम तालुक जिला तेनी

उत्तमपालयम (दक्षिण), उत्तमपालयम (उत्तर), रायप्पनपट्टी, मल्लिंगपुरम, कोहिलापुरम, कोम्बै (पूर्व), कोम्बै (पश्चिम) तथा हनुमंथन पट्टी।

आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं व.)

दिनांक 10 जून 2009

सं. एन-15/13/14/6/2008-यो. व वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम--1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 मई, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा निगम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

केन्द्र

बढ़ते हुए निम्नलिखित क्षेत्र/तेनी जिले के राजस्व गाँव

कंबम उत्तमपालयम जिला तेनी

1. उत्तमपालयम तालुक के कंबम नगरपालिका क्षेत्र

2. उत्तमपालयम तालुक जिला तेनी के राजस्व गाँव

कामयकठण्डनपट्टी, नारायनतेवनपट्टी (दक्षिण), नारायनतेवनपट्टी (उत्तर)

उत्तमपुरम और सी. पुदुपट्टी

आर. सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं व.)

सं. एन-15/13/14/2/2009-यो. व वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम--1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 मई, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा निगम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

केन्द्र

शिवगंगै जिला में

पेरुदुकोट्टै

देवकोट्टै तालुक के करैकुडी उपनगरों

आदि के अन्तर्गत आने वाले राजस्व गाँव

आर. सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं व.)

सं. एन-15/13/10/2/2008-यो. व वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम--1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 मई, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा उड़ीसा कर्मचारी राज्य बीमा निगम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उड़ीसा राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

'डैकनाल जिला के डैकनाल तहसील में नरेन्द्रपुर शिवपुर, फुरुंटी, खडग प्रसाद, तूलसीदिह एवं निमिधा के राजस्व गाँव।'

आर. सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं व.)

सं. एन-15/13/14/10/2009-यो. व वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम--1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में

महानिदेशक ने 1 मई, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा निगम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

केन्द्र

तुतुकोरिन जिला के पुदुक्कोट्टै क्षेत्र

1. मरवनमडम
2. कूताङ्गाडु
3. अल्लिकुलम
4. कुमरगिरी
5. साउत सिलुककानपट्टी
6. सेवैक्कडमडम
7. पेस्वरणी
8. सेन्तिलम्पणै आदि के अन्तर्गत आने वाले राजस्व गाँव

आर. सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं व.)

दिनांक 12 जून 2009

सं. एन-15/13/1/10/2008-यो. व वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 मई, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा निगम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

'आन्ध्र प्रदेश राज्य के महबूबनगर जिले के फारूखनगर मण्डल में स्थित वेलजला-1, 2, 3, और 'केशमपेट' मण्डल में स्थित 'पापीरेड्डीगुडा' के राजस्व ग्रामों की सीमा के अन्तर्गत आने वाले सभी क्षेत्र।'

आर. सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/14/7/2008-यो. व वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 मई, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा निगम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

केन्द्र

चिन्नमनूर

निम्नलिखित बड़े हुए क्षेत्र तेनी जिले के राजस्व गाँव

1. उत्तमपालयम तालुक का चिन्नमनूर नगरपालिका क्षेत्र
2. उत्तमपालयम तालुक जिला तेनी के राजस्व गाँव, पूलानन्तापुरम, करुंकाट्टनकुलम चिन्नावेलापुरम मुत्तलापुरम, मरकायनकोट्टै, पुलिकुत्ति, कुच्चानुर, ओडैपट्टी।

आर. सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग निषेध से सम्बन्धित विश्वविद्यालय²

अनुदान आयोग के अधिनियम, 2009

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 धारा 26 (1) (जी) के अन्तर्गत)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 17 जून 2009

मि० सं० 1-16/2007(सी.पी.पी.-II)

उद्देशिका

माननीय उच्चतम न्यायालय के केरल विश्वविद्यालय बनाम काउंसिल प्रिंसिपल कॉलेज तथा अन्य, एस०एल.पी० सं० 24295, 2006 के 16-5-2007 तथा दिनांक 08-5-2009, सिविल अपील नं. 887 से प्राप्त निर्देशों तथा केन्द्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग निषेध तथा रैगिंग रोकने के संकल्प को ध्यान में रखते हुए। छात्र अथवा छात्रों द्वारा मौखिक शब्दों अथवा लिखित कार्य द्वारा नए अथवा अन्य छात्र को उत्पीड़न, दुर्व्यवहार, छात्र को उत्पात अथवा अनुशासनहीनता की गतिविधियों में सांलिप्त करना जिससे नए अथवा किसी अन्य छात्र को कष्ट, परेशानी, कठिनाई अथवा मनोवैज्ञानिक हानि हो अथवा उसमें भय की भावना उत्पन्न हो अथवा नए या अन्य किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में करे तथा जिससे उसमें लज्जा की भावना उत्पन्न हो अथवा घबराहट हो जिससे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किसी छात्र पर दुष्प्रभाव पड़े अथवा कोई छात्र नए अथवा अन्य छात्र पर शक्ति प्रदर्शन करें। देश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में समुचित विकास हेतु शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अन्य समितियों से विचार विमर्श के पश्चात् ये अधिनियम बनाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 1956 धारा 26 उप खण्ड (जी) उपखण्ड (1) के अधिकारों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, जिसका नाम है—

1. शीर्षक, प्रारम्भ और प्रयोज्यता

- 1.1 ये अधिनियम "विश्वविद्यालय अनुदान के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के अधिनियम, 2009" कहे जाएँगे।
- 1.2 ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा (2) उपखंड (एफ) के अनुसार / विश्वविद्यालय की परिभाषा के अन्तर्गत आनेवाली सभी संस्थाओं तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 1956 धारा 3 के अनुसार सभी डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा अन्य सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं तथा इस प्रकार के विश्वविद्यालय के सम्बन्धित तत्वों से युक्त संस्थाओं, विभागों, इकाइयों तथा अन्य सभी शैक्षिक, आवासीय, खेल के मैदान, जलपान गृह तथा विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं चाहे वे परिसर के भीतर हों अथवा बहार तथा छात्रों के सभी प्रकार के परिवहन चाहे वे सरकारी हों अथवा निजी छात्रों द्वारा इस प्रकार के विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों पर लागू होंगे।

2. उद्देश्य

किसी छात्र अथवा छात्रों के द्वारा दूसरों को मौखिक अथवा लिखित शब्दों द्वारा प्रताड़ित करना, उसे छेड़ना किसी नए छात्र के साथ दुर्य्यवहार करना अथवा उसे अनुशासनहीन गतिविधियों में लगाना जिससे आक्रोश, कठिनाई, मनोवैज्ञानिक हानि हो अथवा किसी नए अथवा अन्य किसी छात्र में भय की भावना उत्पन्न हो अथवा किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में नहीं करे अथवा ऐसा कार्य कराना जिससे उसमें लज्जा की भावना उत्पन्न हो, पीड़ा हो घबराहट हो अथवा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दुष्प्रभाव पड़े अथवा शक्ति प्रदर्शन करना अथवा किसी छात्र का वरिष्ठ होने के कारण शोषण करना। अतः सभी विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा देश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में इन अधिनियम के अन्तर्गत रैगिंग रोकना। इस तरह की घटनाओं में संलिप्त व्यक्तियों को इन अधिनियम तथा विधि के अनुसार दण्डित करना।

3. रैगिंग कैसे होती है—

निम्नलिखित कोई एक अथवा अनेक कार्य रैगिंग के अन्तर्गत आएँगे—

- क किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नए आनेवाले छात्र का मौखिक शब्दों अथवा लिखित वाणी द्वारा उत्पीड़न अथवा दुर्य्यवहार करना।
- ख छात्र अथवा छात्रों द्वारा उत्पात करना अथवा अनुशासनहीनता का वातावरण बनाना जिससे नए छात्र को कष्ट, आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो।
- ग किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में न करे तथा जिससे नए छात्र में लज्जा, पीड़ा, अथवा भय की भावना उत्पन्न हो।
- घ परिष्ठ छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नए छात्र के चलते हुए शैक्षिक कार्य में बाधा पहुँचाए।
- ङ नए अथवा किसी अन्य छात्र का दूसरों को दिए गए शैक्षिक कार्य को करने हेतु बाध्य कर शोषण करना।
- च नए छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना।
- छ शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य/किसी भी प्रकार का यौन शोषण, समलैंगिक प्रहार, नंगा करना, अश्लील तथा काम सम्बन्धी कार्य हेतु विवश करना, अंग चालन द्वारा बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचे।
- ज मौखिक शब्दों द्वारा किसी को गाली देना, ई-मेल, डाक, पब्लिकली किसी को अपमानित करना, किसी को कुमार्ग मार्ग पर ले जाना, स्थानापन्न अथवा कष्टदाय देना या सनसनी पैदा करना जिससे नए छात्र को घबराहट हो।
- झ कोई कार्य जिससे नए छात्र के मन मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े। नए अथवा किसी छात्र को कुमार्ग पर ले लाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना।

4. परिभाषाएँ

- 1 इन अधिनियमों में जब तक कि कोई अन्य संदर्भ न हो।
- क अधिनियम का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956/3) है।
- ख शैक्षिक वर्ष का तात्पर्य किसी संस्था में किसी छात्र का किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश तथा उस वर्ष की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति है।
- ग रैगिंग विरोधी हैल्पलाइन का तात्पर्य इन अधिनियमों के अधिनियम 8.1 की धारा (ए) है।
- घ आयोग का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है।
- ङ समिति (कौंसिल) का तात्पर्य संसद अथवा राज्य के विधानमंडल द्वारा नियमित उच्चतर शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग तथा स्तर बनाए रखने हेतु गठित समिति है। यथा आल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नीकल एजुकेशन (ए.आई.सी.टी.ई.) बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बी.सी.आई.) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डी.सी.आई.) डेन्टिस एजुकेशन काउंसिल (डी.ई.सी.) दी इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च (आइ.सी.ए.आर.) इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आई.एन.सी.) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एम.सी.आई.) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) प्राइमरी काउंसिल ऑफ इंडिया (पी.सी. आई.) इत्यादि तथा राज्यों के उच्चतर शिक्षा काउंसिल इत्यादि।
- च जिला स्तरीय रैगिंग विरोधी समिति का तात्पर्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा रैगिंग रोकने के लिए जिले की परिसीमा में गठित समिति है।
- छ संस्थाध्यक्ष का तात्पर्य विश्वविद्यालय अथवा डीम्ड विश्वविद्यालयों हेतु कुलपति अथवा किसी संस्था का निदेशक, कॉलेज का प्राचार्य सम्बन्धित का कार्यकारी अध्यक्ष है।
- ज "फ़ेशर" से तात्पर्य वह छात्र है जिसका प्रवेश किसी संस्था में हो गया है तथा उस संस्था में उसकी पढ़ाई का प्रथम वर्ष चल रहा है।

- ५ संस्था का तात्पर्य वह उच्चतर शिक्षण संस्था है जो चाहे विश्वविद्यालय हो डीम्ड विश्वविद्यालय हो, कॉलेज अथवा राष्ट्रीय महत्व की कोई संस्थान हो जिसकी रचना संसद के अधिनियम के अनुसार की गई हो। इसमें 12 वर्ष स्कूल की शिक्षा के बाद की शिक्षा दी जाती हो कोई आवश्यक नहीं है कि उसमें चरम सीमा तक उपाधि दी जाती हो। स्नातक/स्नातकोत्तर तथा उच्चतर स्तर अथवा विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र की।
- अ एन.ए.ए.सी. का तात्पर्य आयोग द्वारा अधिनियम की 12(सी.सी.सी.) के अनुसार स्थापित नेशनल एकेडमिक एंड ऐफिडिटेशन काउंसिल है।
- द राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग सेल का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा विधि के अनुसार अथवा केन्द्र सरकार की सलाह पर रैगिंग रोकने के लिए बनाया गया निकाय है। जिसका कार्यक्षेत्र राज्य तक होगा।
- 2 शब्द तथा अभिव्यक्ति को यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम अथवा अधिनियम के सामान्य खण्ड 1887 वही अर्थ होगा जो उसमें दिया गया है।

5. संस्था स्तर पर रैगिंग निषेध के उपाय—

- क कोई भी संस्था अथवा उसका कोई भाग, उसके तत्वों सहित केवल विभागों तक नहीं उसकी संघ तक ईकाई, कॉलेज, शिक्षण केंद्र, उसके भू-गृह चाहे वे शैक्षिक, आवासीय खेल के मैदान अथवा जलपान गृह आदि चाहे वे विश्वविद्यालय परिसर में हो अथवा बाहर, सभी प्रकार के परिवहन, या निजी सभी में रैगिंग रोकने हेतु इन विनियमों के अनुसार तथा अन्य सभी आवश्यक उपाय करेंगे। रिपोर्ट होने पर रैगिंग की किसी भी घटना को दबाया नहीं जाएगा।

- ख सभी संस्थाएं रैगिंग के प्रचार, रैगिंग में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध इन विनियम के अनुसार कार्रवाई करेंगे।

6. संस्था स्तर पर रैगिंग रोकने के उपाय

- 3.1 छात्रों के प्रवेश अथवा पंजीकरण के संदर्भ में संस्था निम्नलिखित कदम उठाए।
- क संस्था द्वारा जारी इलेक्ट्रानिक दृश्य, श्रव्य अथवा प्रिन्ट मीडिया के छात्र को

प्रवेश संबंधी घोषणा में यही बताया जाए कि संस्था में रैगिंग पूर्णतः निषेध है। यदि कोई रैगिंग करने अथवा उसके प्रचार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दोषी पाया गया अथवा रैगिंग प्रचार के षडयंत्र में दोषी पाया गया तो उसे इन विनियम तथा देश के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा।

ख प्रवेश की पुस्तिका के निर्देश पुस्तक तथा विवरण पत्रिका चाहे वे इलेक्ट्रानिक हो अथवा मुद्रित उनमें ये विनियम विस्तार से छापे जाएँ। प्रवेश पुस्तिका का निर्देश पुस्तिका विवरण पत्रिका में यह भी मुद्रित किया जाए कि रैगिंग होने या संस्था के अध्यक्ष इसके साथ संस्थाध्यक्ष, संकाय सदस्य रैगिंग विरोधी समिति के सदस्यों, रैगिंग विरोधी दस्तों के सदस्यों अथवा जिले के अधिकारियों, वार्डनों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के दूरभाष नम्बर प्रवेश पुस्तिका, निर्देश पुस्तिका अथवा विवरण पत्रिका में विस्तार से छापे जाएँ।

ग जहाँ कोई संस्था किसी विश्वविद्यालय से संबंध है वहाँ विश्वविद्यालय यह निश्चित कर ले कि प्रवेश पुस्तिका, निर्देश पुस्तिका यह विवरण पत्रिका प्रकाशित करें तो यह विनियम के विनियम 6.1 के खण्ड (ए) और खण्ड (बी) का अनुपालन करें।

घ प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र, नामांकन अथवा पंजीकरण में एक शपथ पत्र आवश्यक रूप से अंग्रेजी और हिन्दी/अभ्यर्थी की ज्ञात किसी एक प्रादेशिक भाषा में इन विनियम के संलग्नक 1 के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए तथा हस्ताक्षर किया जाए कि उसने किसी अधिनियम के नियमों के पढ़ लिया है तथा इन विनियम के नियमों तथा विनियम के नियमों तथा विधि को समझ लिया है तथा वह रैगिंग निषेध तथा इसके लिए निर्धारित दंड को जानता/जानती है। वह यह घोषण करता/करती है कि उसे किसी संस्था द्वारा निष्कासित/निकाला नहीं गया है। साथ ही वह रैगिंग संबंधी किसी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा/होगी और यदि वह रैगिंग करने अथवा रैगिंग के दुष्प्रेरण का दोषी पाया/पायी गई तो उसे इन विनियम तथा विधि के अनुसार दंडित किया जा सकता है और वह दंड केवल निष्कासन तक सीमिति नहीं होगा।

ङ प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र, नामांकन अथवा पंजीकरण में एक शपथ पत्र अंग्रेजी



आचार्य मनिष र. जोशी
सचिव

Prof. Manish R. Joshi
Secretary



सत्यमेव जयते



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

D. O. No. F. 1-15/2009 (ARC) PLIII

18th April, 2024/29 वैशाख 1946

Respected Madam/Sir,

In pursuance to the Judgment of the Hon'ble Supreme Court of India dated 08.05.2009 in Civil Appeal No. 887/2009, (Copy Attached at Annexure - I) to exercise the powers conferred by clause (g) of sub-section (1) of section 26 of the University Grants Commission Act, 1956, the University Grants Commission (UGC) has notified "Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009". The Regulations are available on the UGC website www.ugc.gov.in & www.antiragging.in.

It is brought to your kind notice that ragging is a criminal offence and UGC has framed *Anti Ragging Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions - 2009* in order to prohibit, prevent and eliminate the scourge of ragging. These regulations are mandatory, and all institutions are required to take necessary steps for its implementation in toto including the monitoring mechanisms. Any violation of these regulations will be viewed seriously. If any institution fails to take adequate steps to prevent ragging or does not act in accordance with these Regulations or fails to punish perpetrators of incidents of ragging suitably, it will attract punitive actions as per UGC Regulations for Curbing the Menace of Ragging - 2009.

As per the orders of Hon'ble Supreme Court a District level Anti - Ragging Committee shall be constituted. The composition of the committee will be as under:

1. District Collector / Deputy Commissioner / District Magistrate - Head of Committee.
2. Head of the concerned University/College/Institutions - Member.
3. Superintendent of Police / SSP of the District - Member.
4. The Additional District Magistrate - Member Secretary.
5. Representative of the Local Media.
6. Representative from District level Non-Government Organizations (Actively associated in youth development programs).
7. Representatives from student organizations.
8. Local Police, Local administration as well the Institutional Authorities to ensure vigil on incidents that may come within the definition of ragging.

This District level Committee should hold preparatory meetings during the summer vacation meetings to take stock of the state of preparedness of each institution and their compliance with the policies and directions or guidelines of the appropriate bodies, the university/State/ Central authorities; and this Court's guidelines in regard to curbing the menace of ragging.

You are also requested to organize publicity campaigns in this regard.

IT IS ONCE AGAIN REITERATED FOR THE BENEFIT OF ALL THE STAKEHOLDERS THAT RAGGING IS A CRIMINAL OFFENCE AND THE CULPRITS WILL ATTRACT PUNITIVE ACTION AS MENTIONED IN THE UGC REGULATIONS.

With kind regards.

Yours sincerely,

(Manish Joshi)

To,

- The Chief Secretary of all States/UTs
- The Collector/SSP/DCP/SP of all Districts.



आचार्य मनिष र. जोशी
सचिव

Prof. Manish R. Joshi
Secretary



सत्यमेव जयते



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

(शिक्षा विभाग, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

D. O. No. F. 1-15/2009 (ARC) Pt.III

18th April, 2024/29 चैत्र 1946

Respected Madam/Sir,

In pursuance to the Judgment of the Hon'ble Supreme Court of India dated 08.05.2009 in Civil Appeal No. 887/2009, to exercise the powers conferred by clause (g) of sub-section (1) of section 26 of the University Grants Commission Act, 1956, the University Grants Commission (UGC) has notified "Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009". The Regulations are available on the UGC website www.ugc.gov.in & www.antiragging.in.

It is once again brought to your kind notice that ragging is a criminal offence and UGC has framed regulations on curbing the menace of ragging in higher educational institutions in order to prohibit, prevent and eliminate the scourge of ragging. These regulations are mandatory, and all institutions are required to take necessary steps for its implementation in toto including the monitoring mechanism. Any violation of these regulations will be viewed seriously. If any institution fails to take adequate steps to prevent ragging or does not act in accordance with these Regulations or fails to punish perpetrators of incidents of ragging suitably, Institutions will attract punitive actions as per UGC Regulations for Curbing the Menace of Ragging – 2009.

You are requested to step up anti-ragging mechanism by way of adequate publicity through various mediums: constitution of Anti-Ragging committee and Anti-Ragging squad, setting up of Anti-Ragging Cell, installing CCTV cameras at vital points, Anti-Ragging workshops and seminar, updating all websites with nodal officers' complete details, alarm bells etc. Regular interaction and counseling with the students, identification of trouble-triggers and mention of Anti-Ragging warning in the institution's E-prospectus and E-information booklets/brochures must be ensured. Surprise inspection of hostels, students' accommodations, canteens, rest cum recreational rooms, toilets, bus-stands must be carried out & Anti-Ragging posters must be displayed at all prominent places like Admission Centre, Departments, Library, Canteen, Hostel, Common facilities etc. These posters are available on UGC website www.ugc.ac.in. The size of the posters should be at least 8x6 feet. Any other measure which would augur well in preventing/quelling ragging and any uncalled-for behavior/incident must be undertaken.

Students in distress due to ragging related incidents can call the National Anti-Ragging Helpline 1800-180-5522 (24x7 Toll Free) or e-mail the Anti-Ragging Helpline at helpline@antiragging.in. For any other information regarding ragging, you may please visit the UGC website i.e. www.ugc.gov.in & www.antiragging.in and contact UGC monitoring agency i.e. Centre for Youth (CY) on Mobile No. 09818044577 (only in case of emergency). In compliance to the directions of the Anti-Ragging Monitoring Committee constituted by Hon'ble Supreme Court of India, HEIs have to implement the following in their institutions:

1. Head of the Universities/Institutions must provide the details of ARC & ARS on the website.
2. Plan for Orientation Programme on Anti Ragging in your Universities/Institutions. The Programme should focus on key aspects of Anti Ragging Regulations and regular feedback of the students after each and every workshop/training/programme should be taken in English, Hindi and Local Language. UGC has made an IEC Kit with suitable content on ragging which is available on UGC website i.e. www.antiragging.in. This kit can be referred for the same.
3. The cultural dadagiri may be controlled by Head of the Universities/Institutions taking police authorities into confidence. In this regard, UGC is also issuing a separate advisory to all District Magistrate/SSP/SP of all districts.

Contd...

(Signature)

CONTINUATION SHEET

-2-

4. The concept of mentor-mentee as given out in the UGC Regulation for Curbing the Menace of Ragging in HEIs - 2009 be followed by students in all institutions to make a comfortable bond amongst Juniors and Seniors.
5. The Anti Ragging Cell and Anti Ragging Squads of institutions should be empowered by provisioning of legal counsel so that airtight cases against the ragging culprits can be made.
6. Henceforth for extreme ragging and suicide cases, Principal of the college and Registrar of the University will be called and will be answerable to the National Anti-Ragging Monitoring Committee for the reasons of non-compliance of UGC Regulations for ragging.
7. All the Councils/Regulatory Bodies must constitute a committee as and when a serious/suicide/death case is reported related to their Council/Regulatory Body to relook into the issue even when case is under police investigation. The Regulatory Bodies/Councils are also advised to appoint a legal person for the matter.
8. The examination (NEET/JEE) causes high stress over students. There is no stress management mechanism available to cope with this. A team of good counsellors with expertise in yoga, meditation and psychology who can read stressful minds to tackle with such problematic cases need to be available. Therefore, a full time counsellor, Yoga/Meditation teacher/instructor may be appointed.
9. The Committee has also instructed the Anti Ragging Monitoring Agency to be more vigilant and carry out surprise checks all across the Nation to ensure that the UGC Regulations to curb the menace of ragging are being strictly adhered to by the HEI's, Teaching Staff and the students. Punitive action as mentioned in these regulations will be taken against the defaulters.

UGC also drives an Anti-Ragging Media Campaign through different modes and has undertaken the following activities to promote the campaign which are available on UGC website www.ugc.gov.in

1. UGC developed 05 TV Commercials of 30 seconds each with different perspective for Parents, Victim and Offenders.
2. UGC designed and distributed 04 types of posters amongst Universities / Regulatory Authorities / Councils / IITs / NITs / other educational institutions for their prominent display.
3. UGC consecutively organized 02 Anti-Ragging Competitions for students/faculty/general public for the wider awareness of the menace of ragging.

In compliance of the 2nd Amendment in UGC Regulations, you are requested to make it compulsory for each student and every parent to submit an online undertaking every academic year at www.antiragging.in

You are also requested to implement the revised procedure for students to file an online Anti- Ragging affidavit. The student will receive an e-mail with his/her registration number. The student will forward that e-mail to the Nodal officer in his/her university/college e-mail

Universities/Colleges have to display the email address and contact number of the Nodal Officer of Anti-Ragging Committee of their university/college on their website and campus areas like Admission Centre, Departments, Library, Canteen, Hostel, and Common facilities, etc.

All HEI's are further advised to fill in the complete details of their respective Anti Ragging Committee and Anti Ragging Squad on the website i.e. www.antiragging.in and also display these lists on the Notice Boards. Universities and Colleges are requested to insert a mandatory column in their university/college's admission form as per the given format:

Anti Ragging Undertaking Reference no:

| |
|--|
| |
|--|

Ami B.

CONTINUATION SHEET

-3-

Universities are also requested to ensure strict compliance of this advisory and fill the compliance on www.antiragging.in. You are also requested to forward this advisory to all the colleges in your ambit with strict compliance directions. All colleges be instructed to make multiple prints of this circular and the same to be prominently displayed at all the locations visited by the students.

IT IS ONCE AGAIN REITERATED FOR THE BENEFIT OF ALL THE STAKEHOLDERS THAT RAGGING IS A CRIMINAL OFFENCE AND THE CULPRITS WILL ATTRACT PUNITIVE ACTION AS MENTIONED IN THE UGC REGULATIONS.

With kind regards,

Yours sincerely,

To,



The Vice-Chancellor/Registrars of all Universities

(Manish Joshi)

INFORMATION EDUCATION COMMUNICATION (IEC)
GUIDELINES FOR COUNCILS, UNIVERSITIES & COLLEGES
Curbing the Menace of Ragging



Ministry of Education
Government of India



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
quality higher education for all



YOU ARE GOING TO FILL AN AFFIDAVIT FOR ANTIRAGGING

TO BE FILLED BY A STUDENT

Fields marked with * are compulsory.

- If you do not have an E mail address please create one before you fill this form.
- If your mother or father or guardian does not have a phone or a mobile phone or email then please give the numbers or email of their friends or relations or neighbours.
- If you do not have a mobile number, then please give the mobile number of your friend of the same college.

After filling out this form successfully, you can download the Student's Anti Ragging Undertaking and the Parents Anti Ragging Undertaking from Website.

The student will receive an e-mail with his/her registration number. The student will forward that e-mail to the Nodal officer in his/her university/college e-mail.

Please note that the student will not receive pdf affidavits and he/she is not required to print & sign them as it used to be in the earlier case

In Case, You have not re

Choose your Educational Institution Type

(Follow ** For Help)

College

Standalone Institution

University

After Successfully Submission of your Affidavit Form, you will receive your **REFERENCE NUMBER**

You can use that to



Anti Ragging Affidavit

- ** College :- Colleges that are affiliated with any university. (Any Regular college)
- ** Standalone Institution :- Institutes which are not dependent on any university.(Teacher Training, Nursing etc)
- ** University :- Universities that provide courses without any colleges. (Same as Regular Courses without any colleges.)

Useful Links

- > [University Grants Commission \(UGC\)](#)
- > [Monitoring Agency, Centre for Youth \(C4Y\)](#)
- > [Ministry of Education \(MoE\)](#)

Useful Links Of This Website

- > [Verify Your Affidavit](#)
- > [Council Login](#)
- > [College Login](#)
- > [Admin Login](#)
- > [NRMC](#)

Sitemap

- > [Home](#)
- > [Fill Affidavits](#)
- > [Fill Compliance](#)
- > [Register Complaint](#)
- > [Give Your Feedback](#)



संस्कृतिकृतिः कला

> Videos on Ragging

Contacts

University Grants Commission (UGC)

Anti Ragging Cell
6, Benito Juarez Marg
South Campus, South Moti Bagh
New Delhi - 110021

National Anti-Ragging Helpline

Phone No :- 1800-180-5522
Email :- helpline@antiragging.in

Monitoring Agency

Centre for Youth (C4Y)

New Delhi - 110068.

Phone No :- 91-11416 19005
Email :- antiragging@c4yindia.org

This website is designed and maintained by the Monitoring Agency, Centre for Youth (C4Y) 

INFORMATION EDUCATION COMMUNICATION (IEC) GUIDELINES FOR COUNCILS, UNIVERSITIES & COLLEGES

© University Grant Commission (UGC), 2022

DISCLAIMER

All rights reserved. The publication is developed as part of University Grant Commission (UGC) National Ragging Prevention Programme for disseminating the information to the Councils, Universities and the Colleges in India.

www.ugc.ac.in

www.antiragging.in and www.c4yindia.org



www.c4yindia.org



**ANTI
RAGGING**

www.antiragging.in



CONTENT

| | |
|---|----|
| Ragging Menace..... | 2 |
| Zero Tolerance Policy in India | 3 |
| Anti-Ragging Regulatory Framework in India | 4 |
| Important Links for the Students, Colleges, Universities and Councils | 7 |
| Higher Education Institutions in India (HEIs) | 8 |
| Awareness Measures for Ragging free Campuses | 9 |
| Awareness Collaterals | 10 |

ABBREVIATIONS

| | | | |
|-------|--|------|--|
| ACP | Assistant Commissioner of Police | INC | Indian Nursing Council |
| AICTE | All India Council of Technical Education | IT | Information Technology |
| ARC | Anti-Ragging Committee | MCI | Medical Council of India |
| ASP | Assistant Superintendent of Police | NCRI | National Council for Rural Institutes |
| BCI | Bar Council of India | NCTE | National Council for Teacher Education |
| C4Y | Centre for Youth | PCI | Pharmacy Council of India |
| CCH | Central Council of Homeopathy | RCI | Rehabilitation Council of India |
| CCIM | Central Council for Indian Medicine | SCHE | State Councils of Higher Education |
| COA | Council of Architecture | SHO | Station House Officer |
| DCI | Dental Council of India | SP | Superintendent of Police |
| DCP | Deputy Commissioner of Police | SPC | Statutory Professional Councils |
| FAQ | Frequently Asked Question | SSP | Senior Superintendent of Police |
| ICAR | Indian Council for Agricultural Research | UGC | University Grants Commission |
| IEC | Information Education Communication | | |

RAGGING MENACE

Ragging is a disturbing reality in the higher education system of our country. Despite the fact that over the years, ragging has claimed hundreds of innocent lives and has ruined the careers of thousands of bright students, the practice is still perceived by many as a way of 'familiarisation' and an 'initiation into the real world' for young college-going students.

The Ragging is defined as any disorderly conduct, whether by words spoken or written or by an act, has the effect of teasing, treating, or handling with rudeness a fresher or a junior student. Indulging in a rowdy or undisciplined activity that causes or is likely to cause annoyance, hardship, or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in a fresher or junior student. Asking the students to do any act or perform something that such students will not do in the ordinary course and which has the effect of causing or generating a sense of shame or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of a fresher or junior student. This can lead to adverse effects such as depression, anxiety, and sometimes even suicide.

Punishment Provisions

Any student or group of students found guilty of ragging on campus or off campus shall be liable to one or more of the following punishments:

- Debarring from appearing in any sessional test/ university examination or withholding results
- Suspension from attending classes and academic privileges
- Withdrawing scholarships and other benefits
- Suspension from the college for a period of one month
- Cancellation of admission
- Debarring from representing the institution in any national or international meet, tournament, youth festival, etc
- Suspension/expulsion from the hostel
- Rustication from the institution for periods varying from 1 to 4 semesters or equivalent period
- Expulsion from the institution and consequent debarring from admission to any other institution
- Fine up to twenty five thousand rupees
- Imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both
- Collective punishment - When the students committing or abetting the crime of ragging are not identified, the institution shall resort to collective punishment as a deterrent to ensure community pressure on the potential raggers.

Any institution that fails to take adequate steps to prevent ragging or fails to act in accordance with the Regulations or fails to punish perpetrators or incidents of ragging suitably is liable to the penalties and punishments as per the provisions of the Regulations.

www.antiragging.in/assets/pdf/information/english/what_constitutes_ragging.pdf

www.c4yindia.org/Home/AntiRagging

ZERO TOLERANCE POLICY IN INDIA

No act of ragging, major or minor, shall go unnoticed. No ragger, male or female, student or non-student, shall go unpunished. No institution that fails to take action against ragging shall be allowed to operate.

The Supreme Court, in its judgement dated 08 May 2009 ordered the implementation of a ragging prevention programme comprising, inter alia, setting up a toll-free anti-ragging helpline/ call center, a database of institutions/ students, and engaging an independent non-government agency as the monitoring agency.

Regulatory provisions and the appropriate law are in force to eliminate ragging in all its forms from the universities, deemed universities and other higher educational institutions in the country by prohibiting, preventing its occurrence and punishing those who indulge in ragging.

UGC Regulations on curbing the menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009

Ragging is a criminal offense and UGC has framed regulations on curbing the menace of ragging in higher educational institutions in order to prohibit, prevent and eliminate the scourge of ragging. In pursuance to the Judgment of the Hon'ble Supreme Court of India dated 08.05.2009 in Civil Appeal No. 887/2009, in exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (1) of section 26 of the University Grants Commission Act, 1956, the UGC notified "Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009". These regulations are mandatory for all universities/ institutions.



Notices @ UGC
www.ugc.ac.in/ugc_notices.aspx



UGC Regulations
www.antiragging.in/assets/pdf/annexure/Annexure-I.pdf

ANTI-RAGGING REGULATORY FRAMEWORK IN INDIA

▶ Anti-Ragging Monitoring Committee, Ministry of Education, Government of India

The Anti-Ragging Committee for monitoring measures to prevent ragging in higher educational institutions is constituted in the Ministry of Education, Government of India.

▶ University Grant Commission (UGC)

As per the directions of the Government of India, the UGC established the following regulatory framework mechanism to curb the menace of ragging in the country.



▶ UGC Anti-Ragging Cell

The Anti-Ragging Cell within UGC is an instructional mechanism to provide secretarial support for the collection of information, monitoring and to coordinate with the State Level Monitoring Cell and Universities Level Committees for effective implementation of anti-ragging measures. The Cell also coordinates with the Monitoring Agency.

▶ Inter Council Committee, UGC

The UGC has constituted an Inter-Council Committee, consisting of representatives of the various Councils and the Monitoring Agency. Such bodies in higher education are to coordinate and monitor the anti-ragging measures in institution across the country and to make recommendations from time to time.

▶ The National Anti-Ragging Helpline

The National Anti-Ragging Help Line 24x7 Toll Free number is 1800-180-5522. The support is provided for queries related to ragging, complaint registration, among others.

▶ Monitoring Agency

The Centre for Youth (C4Y) is the Monitoring Agency from April 01, 2022 (www.c4yindia.org) to support the National Ragging Prevention Programme in the country. The monitoring agency is working towards:

1. Establishing the National 24x7 Anti-Ragging Helpline
2. Software development (IT) for the operation of the national anti-ragging helpline
3. Development and updating the anti-ragging website (www.antiragging.in) and monitoring agency website (www.c4yindia.org)
4. Building an online reporting mechanism for UGC, councils, universities and colleges
5. Conducting trainings of helpline executives
6. Supervising the performance of the helpline and executives
7. Ensuring efficiency and ease of operations for the national helpline, UGC, colleges, universities, and the students
8. Creating awareness to demote ragging in universities, colleges across India
9. Monitoring of the databases maintained by the commission

The Councils, Regulatory Bodies

The 15 councils in India are making collaborative efforts with UGC to address the menace of ragging. They have been issuing directions and monitoring the affiliated universities and colleges for adhering to the regulatory provisions and compliances. They participate in UGC Inter-Council meetings and the Anti-Ragging Monitoring Committee meetings of the Ministry of Education, Government of India for updates and strategies. The councils are:

1. All India Council of Technical Education (AICTE)
2. Bar Council of India (BCI)
3. Council of Architecture (COA)
4. Dental Council of India (DCI)
5. Indian Council for Agricultural Research (ICAR)
6. Indian Council of Medical Research (ICMR)
7. Indian Nursing Council (INC)
8. Mahatma Gandhi National Council of Rural Education (MGNCRE)
9. National Commission for Homoeopathy (NCH)
10. National Commission for Indian System of Medicine (NCISM)
11. National Council for Hotel Management & Catering Technology (NCHMCT)
12. National Council for Teacher Education (NCTE)
13. National Medical Commission (NMC)
14. Pharmacy Council of India (PCI)
15. Rehabilitation Council of India (RCI)
16. Sports Authority of India (SAI)
17. Veterinary Council of India (VCI)

The Anti-Ragging Committee (ARC), Universities and Colleges

The Anti-Ragging Committee is instituted at each college or university to ensure compliance with the provisions of the regulations as well as the provisions of any law for the time being in force concerning ragging; investigate complaints and also, monitor and oversee the performance of the Anti-Ragging Squad in prevention of ragging in the institution. The Anti-Ragging Committee is responsible for inculcating a culture of Ragging Free Environment on Campus. The Anti-Ragging Committee is involved in designing strategies and action plan for curbing the menace of ragging in the college by adopting an array of activities. The committee is also responsible for conducting awareness programmes from time-to-time on campus.

Anti-Ragging Squads, Universities and Colleges

The Anti-Ragging Squad office bearers work under the supervision and guidance of the Anti-Ragging Committee and engage in checking places like hostels, buses, canteens, grounds, classrooms and other places of student congregation to keep a vigil and stop the incidences of ragging, if any, and report them if they happen. The squad role is also to educate the students at large by adopting various means about the menace of ragging and related punishments there to.

► Transparent Complaint Process

Specifically, after registering the complaint, the helpline executives forward it to four Higher Authorities:

University Vice-Chancellor | College Principal | SHO | City SP/SSP/DCP/ASP/ACP | Council

The team at the national helpline undertakes follow-up with the college's Anti-Ragging Committee (ARC) for investigation and ARC report till the satisfaction of the victim/ complainant. The complaint remains active in the helpline until the victim/ complainant is satisfied with the action taken by the authorities. The consent in writing for closing the complaint is taken from the victim/ complainant.

If the case is not resolved to the satisfaction of the victim/ complainant, the national helpline escalates the case to the Monitoring Agency for further action in terms of advice, second opinion, or follow-up by the Monitoring agency itself.

If the complainant is not satisfied with the action taken by the college or the college authorities are not cooperating with the helpline centre, such cases are escalated to the University Grants Commission and the respective council for intervention.

There is an online management system set up in the UGC premises for UGC to act on the complaints that have been escalated to UGC. Any actions in terms of writing a letter, email, phone calls etc. are being logged into the case file of the respective complaint. The case file is also visible to the victim/ complainant - www.ugc.ac.in

The status of the complaint with complete follow-up can be accessed at the link below with specific complaint number:



Enter Complaint Number To Check Status

Complaints Registered Before April 2012

Complaints Registered From April 2012

www.antiragging.in

Note: The helpline NEVER discloses the identity of the victim without their permission and consent.

Ragging Complaints Registration

The students in distress due to ragging-related incidents can contact National Anti-Ragging Helpline 1800-180-5522 (24x7 Toll Free) or e-mail to helpline@antiragging.in.

Or

They may also contact UGC Monitoring Agency i.e. Centre for Youth (C4Y) at antiragging@c4yindia.org or 011-41619005 or 98180 44577 (only in case of emergency).

IMPORTANT LINKS FOR THE STUDENTS, COLLEGES, UNIVERSITIES AND COUNCILS

► Students and Parents Undertaking Affidavit

In compliance of the second amendment in UGC Regulations, it is compulsory for each student and every parent to submit an online Anti-Ragging undertaking affidavit every academic year. The universities and colleges are also requested to implement the revised procedure for students to file online Anti-Ragging affidavits. The student will receive an e-mail with her/ his registration number. The student will forward that e-mail to the Nodal officer in her/ his university/college e-mail. (Please note that the student will not receive pdf affidavits and she/ he is not required to print & sign it as it used to be in the earlier case).

Link to fill out the online undertaking affidavit by students and parents:

www.antiragging.in/affidavit_registration_disclaimer.html | www.c4yindia.org/Home/Undertaking

► Ragging Complaints Registration

The complaints of ragging are being registered through the following means:

1. Via e-mail: helpline@antiragging.in
2. National Anti-Ragging Help Line: 1800-180-5522. 24x7 Toll Free Number
3. Suo Motto via Social Media platforms, news, reporters, influencers, social workers among others

Links for filling out ragging complaints:

The National Anti-Ragging Helpline website - www.antiragging.in

The Monitoring Agency website - www.c4yindia.org

► Universities and Colleges Compliance

The UGC regulation has made it mandatory for the universities and colleges to demote ragging in their campuses and follow the compliances to achieve these objectives. The universities are requested to fill online compliance and also immediately instruct all the colleges under their purview to follow it.

Link for 'confirmation on compliance being followed':

www.antiragging.in/compliance_disclaimer.html | www.c4yindia.org/Home/CollegeCompliance

► Colleges and Universities Contact Details

As per the order of the Hon'ble Supreme Court, it is mandatory for the college and university authorities to update their details each year, so that college students can navigate the college or university details while filing the undertaking affidavit.

Link to update college or university details:

www.antiragging.in/compliance_disclaimer.html | <https://www.c4yindia.org/Home/UpdateCollCont>

► Councils Reporting

The various councils in India are the statutory bodies for regulating universities and colleges. The measures undertaken by them to curb the menace of ragging in their respected affiliated universities and colleges are to be mandatorily reported.

Link to upload the council's reports:

www.antiragging.in/admin/login.php

HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN INDIA (HEIs)

UGC Regulations on 'Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009' are mandatory and all higher education institutions are required to take necessary steps for its implementation including the monitoring mechanism. Any violation of these regulations will be viewed seriously. If any institution fails to take adequate steps to prevent ragging or does not act in accordance with these Regulations or fails to punish perpetrators of incidents of ragging suitably, it will attract punitive action against itself by the UGC.

The requisite mandatory action for curbing the menace of ragging in all Higher Educational Institutions in India:

- Strengthen and augment anti-ragging mechanism by way of adequate publicity through various mediums
- Constitution of Anti-Ragging committee and Anti-Ragging squad
- Establish Anti-Ragging Cell
- Install CCTV cameras at vital points
- Organise anti-ragging interaction, workshops and seminars for the freshers and the senior students
- After the commencement of the academic year organised professional counselling of the students
- Ensure identification of trouble triggers and take appropriate action
- Mention of Anti-Ragging warnings in the institution's E-prospectus and E-Information booklets/ brochures
- Conduct surprise inspections of hostels, students, accommodation, canteens, rest cum recreational rooms, toilets, bus stands, and all other strategic locations
- Undertake all other measures that would augur well in preventing/ quelling ragging and any uncalled-for behaviour and the incident.

Website with nodal officers' complete details

Universities/ colleges have to display the email address and contact number of the Nodal Officer of the Anti-Ragging Committee of their university/ college on their website and campus areas like Admission Centre, Departments, Library, Canteen, Hostel, Common facilities, etc.

Admission Form

Universities and colleges are requested to insert a mandatory column in their university/ colleges admission form as per the given format:

| | |
|--|--|
| Anti-Ragging Undertaking Reference no: | |
|--|--|

AWARENESS MEASURES FOR RAGGING FREE CAMPUSES

- Every public declaration of intent by any institution in electronic, audio-visual, online, social media, print, website, admission prospectus/ booklet or any other media should expressly mention that ragging is totally prohibited in the institution at the time of admission of students in any course.
- The brochure of admission/ instruction booklet or prospectus, whether in print or electronic format, shall prominently print these regulations in full.
- Institutions should display posters in all prominent locations showcasing the provisions of penal law applicable to incidents of ragging.
- At the end of each academic year, the institution should send a letter to the parents/ guardians informing them about the Regulations and any law for the time being enforced prohibiting ragging and its punishments.
- Institutions can issue public notices in the newspapers, update their websites with the nodal officer's complete details.
- Every fresher should be provided with a printed leaflet with all the information to seek help and guidance from all authorities and agencies, and a calendar of events and activities laid down by the institution to facilitate and complement the familiarisation of freshers with the academic environment of the institution.
- Institutions should conduct joint sensitisation and orientation programmes for both freshers and senior students.
- Institutions should constitute Anti-Ragging Committee and Anti-Ragging Squad which will be responsible for spreading awareness and preventing the occurrence of ragging.
- Meeting of all staff, functionaries and agencies before the commencement of the academic session.
- Institutions should launch a publicity campaign against ragging before the commencement of the academic year.
- After the commencement of the academic year, the batch of freshers should be divided into small groups and assigned to the faculty for difficulties and guidance.
- Random anonymous survey should be done among students about ragging, and it should be a regular practice in the institution.

In Nutshell

- Brochure of admission/instruction booklet or the prospectus
- Leaflets
- Posters
- Institution website
- Meetings
- Publicity campaign
- Seminars and workshops
- Professional counselling
- Orientation programmes
- Large scale cultural, sports and other activities

▶ UGC designed and distributed four types of posters amongst Universities/ Regulatory Authorities/ Councils/ IITs/ NITs/ other educational institutions for their prominent display. These anti-ragging posters must be displayed at all prominent places like the Admission centre, Departments, Library, canteen, Hostel, Common facilities, etc. These posters are available on UGC website. The size of the posters should be 8x6 feet.

▶ UGC developed 05 TVCs of 30 seconds each with different perspectives i.e. Parents, victims, and Offenders.

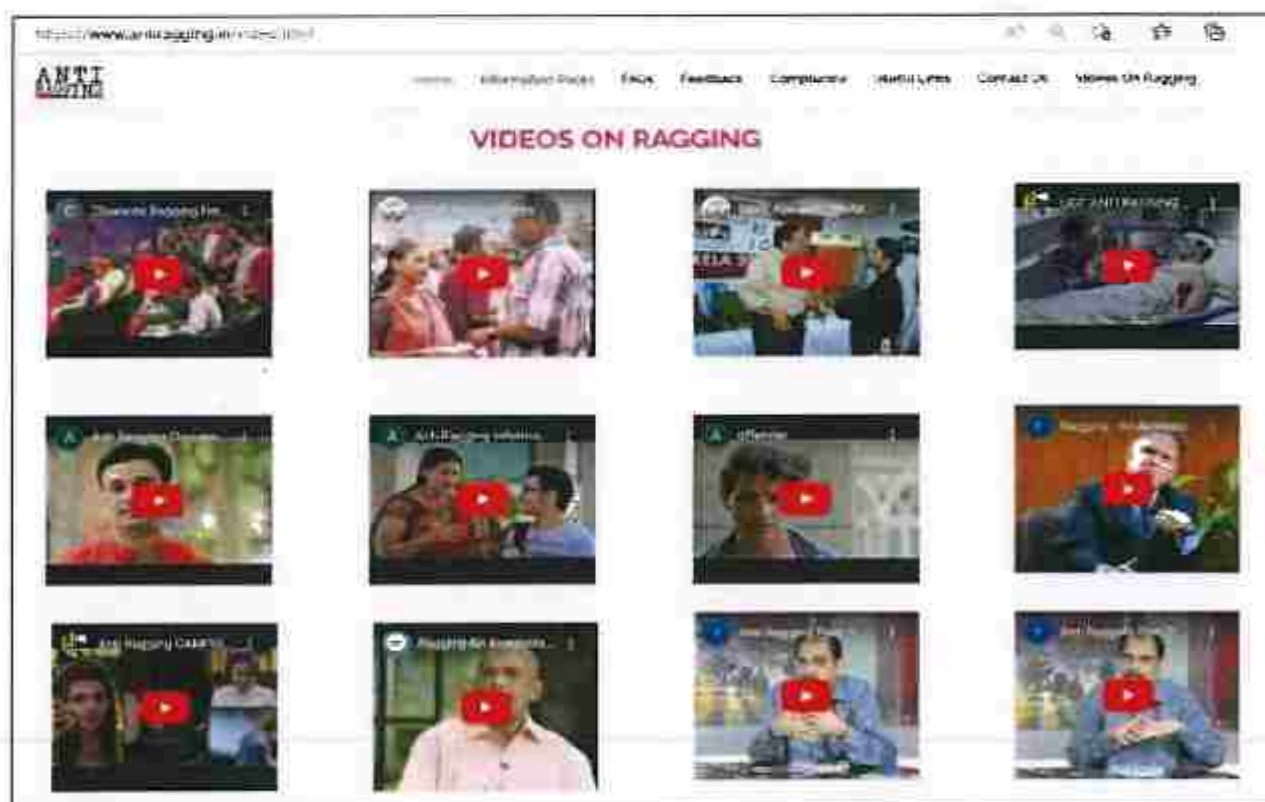
AWARENESS COLLATERALS

► Posters



Download: www.ugc.ac.in/pdf/news/4957638_poster-ragging.pdf

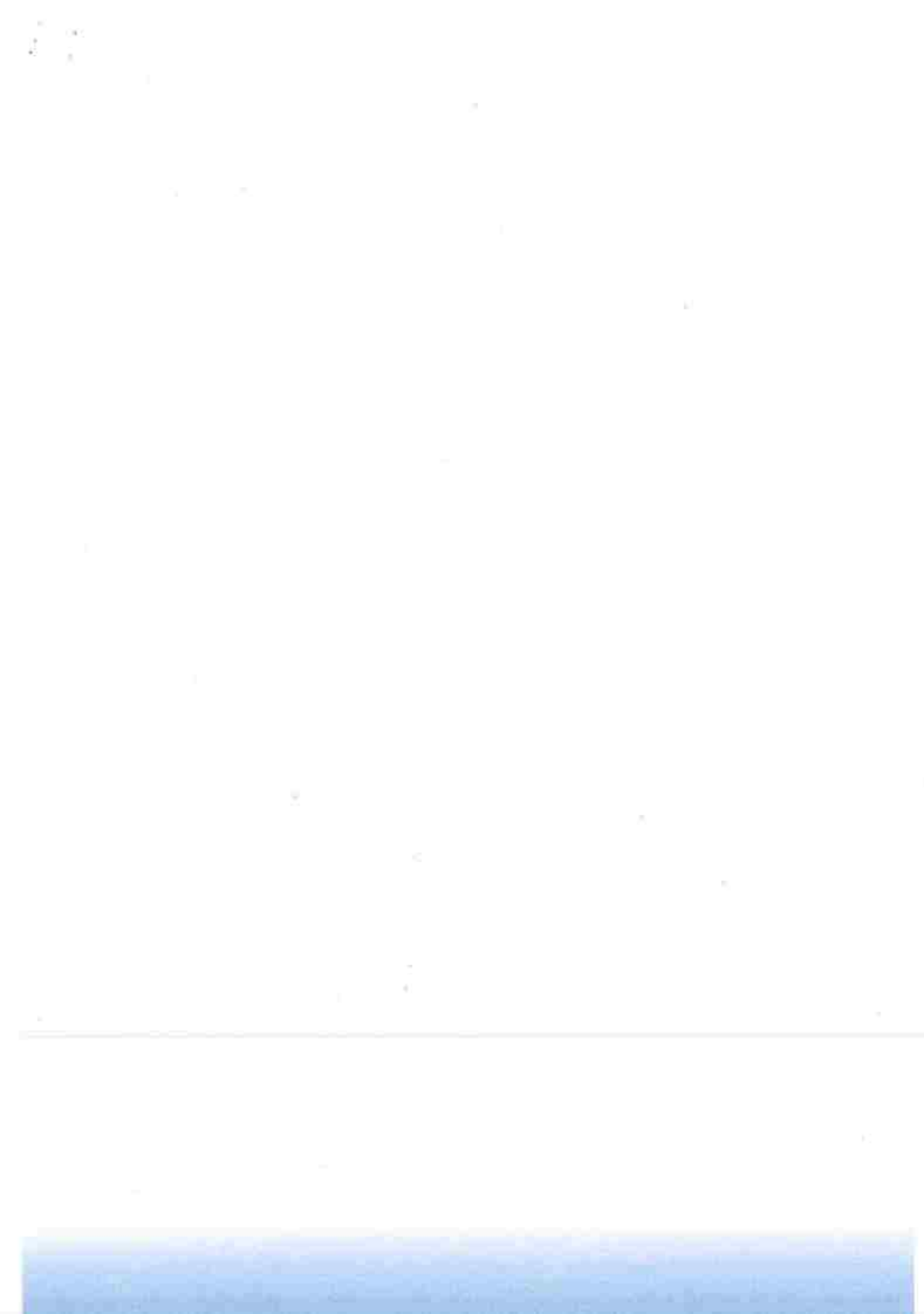
► Videos



www.antiragging.in/video.html

► Frequently Asked Questions (FAQ)

www.antiragging.in/faqs.html | www.c4yindia.org/Home/AntiRagging



REACH OUT

University Grant Commission (UGC)

Bahadur Shah Zafar Marg
New Delhi 110 002
P: 91 11 2360 4446; 2360 4200
E: contact.ugc@nic.in

UGC Anti-Ragging Cell (ARC)

NET Bureau, South Campus of Delhi University,
Benito Jhuarez Marg, New Delhi 110 021
P: 91 11 2411 2087
E: raggingcell@yahoo.in

Monitoring Agency

Centre for Youth (C4Y)
New Delhi 110 068
P: 91 11 4161 9005
E: antiragging@c4yindia.org

National Anti-Ragging Helpline

New Delhi 110 007
P: 1800 180 5522
E: helpline@antiragging.in

NATIONAL RAGGING PREVENTION PROGRAMME

www.ugc.ac.in

www.antiragging.in and www.c4yindia.org

Dr. Dev Swarup

संयुक्त सचिव
Joint Secretary



दूरभाष PHONE कार्यालय OFF : 011-23231273

फैक्स FAX : 011-23231291

E-mail : dev@ugc.ac.in

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुर शाह ज़फर मार्ग,

नई दिल्ली-110 002 (भारत)

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

BAHADUR SHAH ZAFAR MARG

NEW DELHI-110 002 (INDIA)

No.F.1-113/ 2009(CPP-II)

September, 2009

Register

All Universities

12 OCT 2009

Subject: UGC Regulations on curbing the menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009.

Sir,

In continuation to this office letter of even no. dated 7th July, 2009 on the above subject, I am enclosing a copy of the UGC Regulations on curbing the menace of ragging in educational institutions, 2009 published in the Gazette of India dt.4th July,2009 in (i) English and (ii) Hindi) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रेगिंग निषेध से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम, 2009 for your information and necessary action.

The above regulations are mandatory and shall apply to all Universities established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State/Union Territory Act and all Institutions recognised by or affiliated to such Universities and all Institutions deemed to be Universities under Section (3) of the UGC Act, 1956 with effect from 4th July, 2009 i.e. the date of its Publication in the official Gazette.

It is requested that these regulations may please be brought to the notice of the Colleges affiliated to your Universities/Institution.

Yours faithfully,

(Dev Swarup)
Joint Secretary

Encl: As above

O/C

Copy to:-

1. All States/ U.Ts Higher. Education Secretaries (List attached).
2. The Secretary, Govt. of India/Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi-110001
3. Shri V. Umashankar, Director, Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi-110001
4. The Secretary, Association of Indian Universities (AIU), 16, Comrade Inderjit Gupta Marg (Kotla), New Delhi-110002
5. All Professional Councils.
6. Ps to Chairman/Ps to Vcm/Ps to Secretary, UGC, New Delhi
7. JS (Web site) UGC for posting on UGC website.
8. All Regional Offices, UGC.
9. Guard file

वि. जामसवाल
(V.K. Jaiswal)
Deputy Secretary
26.10.200
O/c



आचार्य मनिष र. जोशी
सचिव

Prof. Manish R. Joshi
Secretary



सत्यमेव जयते



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

D. O. No. F. 1-15/2009 (ARC) Pl.III

18th April, 2024/29 चैत्र 1946

Respected Madam/Sir,

In pursuance to the Judgment of the Hon'ble Supreme Court of India dated 08.05.2009 in Civil Appeal No. 887/2009, to exercise the powers conferred by clause (g) of sub-section (1) of section 26 of the University Grants Commission Act, 1956, the University Grants Commission (UGC) has notified "Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009". The Regulations are available on the UGC website www.ugc.gov.in & www.antiragging.in.

It is once again brought to your kind notice that ragging is a criminal offence and UGC has framed regulations on curbing the menace of ragging in higher educational institutions in order to prohibit, prevent and eliminate the scourge of ragging. These regulations are mandatory, and all institutions are required to take necessary steps for its implementation in toto including the monitoring mechanism. Any violation of these regulations will be viewed seriously. If any institution fails to take adequate steps to prevent ragging or does not act in accordance with these Regulations or fails to punish perpetrators of incidents of ragging suitably, Institutions will attract punitive actions as per UGC Regulations for Curbing the Menace of Ragging - 2009.

You are requested to step up anti-ragging mechanism by way of adequate publicity through various mediums; constitution of Anti-Ragging committee and Anti-Ragging squad, setting up of Anti-Ragging Cell, installing CCTV cameras at vital points, Anti-Ragging workshops and seminar, updating all websites with nodal officers' complete details, alarm bells etc. Regular interaction and counseling with the students, identification of trouble-triggers and mention of Anti-Ragging warning in the institution's E-prospectus and E-information booklets/brochures must be ensured. Surprise inspection of hostels, students' accommodations, canteens, rest cum recreational rooms, toilets, bus-stands must be carried out & Anti-Ragging posters must be displayed at all prominent places like Admission Centre, Departments, Library, Canteen, Hostel, Common facilities etc. These posters are available on UGC website www.ugc.ac.in. The size of the posters should be at least 8x6 feet. Any other measure which would augur well in preventing/quelling ragging and any uncalled-for behavior/incident must be undertaken.

Students in distress due to ragging related incidents can call the National Anti-Ragging Helpline 1800-180-5522 (24x7 Toll Free) or e-mail the Anti-Ragging Helpline at helpline@antiragging.in. For any other information regarding ragging, you may please visit the UGC website i.e. www.ugc.gov.in & www.antiragging.in and contact UGC monitoring agency i.e. Centre for Youth (C4Y) on Mobile No. 09818044577 (only in case of emergency). In compliance to the directions of the Anti-Ragging Monitoring Committee constituted by Hon'ble Supreme Court of India, HEIs have to implement the following in their institutions:

1. Head of the Universities/Institutions must provide the details of ARC & ARS on the website.
2. Plan for Orientation Programme on Anti Ragging in your Universities/Institutions. The Programme should focus on key aspects of Anti Ragging Regulations and regular feedback of the students after each and every workshop/training/programme should be taken in English, Hindi and Local Language. UGC has made an IEC Kit with suitable content on ragging which is available on UGC website i.e. www.antiragging.in. This kit can be referred for the same.
3. The cultural dadagiri may be controlled by Head of the Universities/Institutions taking police authorities into confidence. In this regard, UGC is also issuing a separate advisory to all District Magistrate/SSP/SP of all districts.

Contd...

(Signature)

CONTINUATION SHEET

-2-

4. The concept of mentor-mentee as given out in the UGC Regulation for Curbing the Menace of Ragging in HEIs - 2009 be followed by students in all institutions to make a comfortable bond amongst Juniors and Seniors.
5. The Anti Ragging Cell and Anti Ragging Squads of institutions should be empowered by provisioning of legal counsel so that airtight cases against the ragging culprits can be made.
6. Henceforth for extreme ragging and suicide cases, Principal of the college and Registrar of the University will be called and will be answerable to the National Anti-Ragging Monitoring Committee for the reasons of non-compliance of UGC Regulations for ragging.
7. All the Councils/Regulatory Bodies must constitute a committee as and when a serious/suicide/death case is reported related to their Council/Regulatory Body to relook into the issue even when case is under police investigation. The Regulatory Bodies/Councils are also advised to appoint a legal person for the matter.
8. The examination (NEET/IT JEE) causes high stress over students. There is no stress management mechanism available to cope with this. A team of good counsellors with expertise in yoga, meditation and psychology who can read stressful minds to tackle with such problematic cases need to be available. Therefore, a full time counsellor, Yoga/Meditation teacher/instructor may be appointed.

9. The Committee has also instructed the Anti Ragging Monitoring Agency to be more vigilant and carry out surprise checks all across the Nation to ensure that the UGC Regulations to curb the menace of ragging are being strictly adhered to by the HEI's, Teaching Staff and the students. Punitive action as mentioned in these regulations will be taken against the defaulters.

UGC also drives an Anti-Ragging Media Campaign through different modes and has undertaken the following activities to promote the campaign which are available on UGC website www.ugc.gov.in

1. UGC developed 05 TV Commercials of 30 seconds each with different perspective for Parents, Victim and Offenders.
2. UGC designed and distributed 04 types of posters amongst Universities / Regulatory Authorities / Councils / IITs / NITs / other educational institutions for their prominent display.
3. UGC consecutively organized 02 Anti-Ragging Competitions for students/faculty/general public for the wider awareness of the menace of ragging.

In compliance of the 2nd Amendment in UGC Regulations, you are requested to make it compulsory for each student and every parent to submit an online undertaking every academic year at www.antiragging.in

You are also requested to implement the revised procedure for students to file an online Anti- Ragging affidavit. The student will receive an e-mail with his/her registration number. The student will forward that e-mail to the Nodal officer in his/her university/college e-mail

Universities/Colleges have to display the email address and contact number of the Nodal Officer of Anti-Ragging Committee of their university/college on their website and campus areas like Admission Centre, Departments, Library, Canteen, Hostel, and Common facilities, etc.

All HEI's are further advised to fill in the complete details of their respective Anti Ragging Committee and Anti Ragging Squad on the website i.e. www.antiragging.in and also display these lists on the Notice Boards. Universities and Colleges are requested to insert a mandatory column in their university/college's admission form as per the given format:

Anti Ragging Undertaking Reference no:

Ami

CONTINUATION SHEET

-3-

Universities are also requested to ensure strict compliance of this advisory and fill the compliance on www.antiragging.in. You are also requested to forward this advisory to all the colleges in your ambit with strict compliance directions. All colleges be instructed to make multiple prints of this circular and the same to be prominently displayed at all the locations visited by the students.

IT IS ONCE AGAIN REITERATED FOR THE BENEFIT OF ALL THE STAKEHOLDERS THAT RAGGING IS A CRIMINAL OFFENCE AND THE CULPRITS WILL ATTRACT PUNITIVE ACTION AS MENTIONED IN THE UGC REGULATIONS.

With kind regards,

Yours sincerely,



(Manish Joshi)

To,

The Vice-Chancellor/Registrars of all Universities

Copy to:

1. Ms. Rina Sonowal, Joint Secretary, Higher Education, MoE. (rinasonowal.edu@nic.in)
2. All Regulatory Authorities
3. Ms. Jasleen Kaur, Under Secretary, Ministry of Education, (jasleen.kau@nic.in).
4. JS/DS (website), UGC (for uploading on (i) UGC website, (ii) Under ragging related Twitter handle of UGC)
5. Ms. Alka Tomar, Centre for Youth (C4Y) (alka.tomar@c4yindia.org) (for uploading on antiragging.in)



(Manish Joshi)